संख्या 366 / XXXIV / 2014 / 20 / 2012

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। देहरादून: दिनांक 08 अगस्त 2014

विषय:- प्रदेश में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

भारत सरकार की नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर (OFC) केबल बिछाये जाने है। उक्त कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा स्पेशल परपज वेहिकिल के रूप में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) का चयन किया गया है। उक्त परियोजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध मे राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार एव भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन दिनांक 26.10.2012 (प्रति संलग्न) का हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

2 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित व्यवस्थाए लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:--

(1) नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित किये जाने हेतु ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने के सम्बन्ध मे विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व में पडने वाले भूमि की खुदाई से पूर्व विभिन्न स्तरों से अनुमति प्राप्त करने में आने वाली जटिलताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड [illegible] प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन [illegible] प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न संस्थाओ से परियोजनावधि में पुन अनुमति न लेनी पडे, इस हेतु ब्लैंकेट अप्रूवल एतदद्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अन्तर्गत आप्टिकल फाइबर केबल (OFC) बिछाने हेतु नि:शुल्क अनुमति एवं अधिकार (ROW) होगा तथा कोई भी रीइन्स्टेटमेंट शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(2) उक्त समझौता ज्ञापन के प्रस्तर- 5.2 में की गयी व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत तक आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा की जायेगी। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा रीइन्स्टेटमेंट का कार्य इस भाँति किया जायेगा कि सड़क के किनारे खोदी गयी सतह भरसक उसकी मूल स्थिति में ले आई जाए। सडक की कटान को न्यून करने के लिए यथाशक्ति प्रयास किया जायेगा। पक्की सडक

Endo. No:— UK(?)/CFA/NOFN/Tender (Con)/13-14/24 Dt- 19/8/14
Copy to:— ① All SSA Heads of UKD Circle for info. & n/a,
② DGM (TP-II) Dehradun for info. & n/a.

सहायक महाप्रबंधक (बी.डी.)
कार्या. मुख्य महाप्रबंधक (बी.एस.एन.एल.)
उत्तराखण्ड दूरसंचार परिमंडल, देहरादून

को पार करने के लिए एच०डी० अथवा हॉरिजन्टल बोरिंग का प्रयोग किया जा... ताकि सड़क को ... वाली क्षति को ... से ... किया जा सके।

(3) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समन्वय के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

(4) चूँकि ग्राम पंचायतों तक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना स्थानीय जनता, ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार के हित में है अतः राज्य सरकार के स्थानीय निकाय, राज्य सरकार की कम्पनियों तथा एजेंसियों द्वारा राइट ऑफ वे (ROW) चार्जेज अधिरोपित नहीं किये जायेंगे। इस परियोजना में राज्य सरकार का अंशदान माना जायेगा।

(5) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायत कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने हेतु स्थापित किये जाने वाले OPGW / ABSS केबिलों की स्थापना के लिए राज्य सरकार की वितरण कंपनियों / पारेषण कंपनियों द्वारा वितरण लाइनों / पारेषण लाइनों / उप पारेषण लाइनों पर शुल्क रहित राइट ऑफ वे प्रदान किया जायेगा।

(6) परियोजना से सम्बन्धित उपकरणों की स्थापना / उपकरण को रखने के लिए यथाआवश्यक शुल्क भुगतान के आधार पर ग्राम पंचायत भवन अथवा अन्य समुचित स्थान पर स्थल एवं बिजली उपलब्ध कराई जाएगी तथा ऐसे स्थानों पर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के स्टाफ अथवा प्रतिनिधि को ऑपरेशन एवं मेन्टीनेन्स के लिए अनुमति होगी।

(7) जनपद स्तर पर परियोजना के निर्विघ्न, सफल एवं सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिए निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति गठित की जायेगी:--

1- जिलाधिकारी- अध्यक्ष
2--मुख्य विकास अधिकारी- सदस्य सचिव
3-अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग- सदस्य
4-अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा- सदस्य
5-अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, विद्युत विभाग- सदस्य
6-अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग- सदस्य
7-अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष पेयजल विभाग- सदस्य
8-प्रभागीय वनाधिकारी- सदस्य
9-जिला पंचायतीराज अधिकारी- सदस्य
10-सम्बन्धित मुख्य नगर अधिकारी / नगर अधिकारी- सदस्य
11-अन्य जिलाधिकारी द्वारा नामित- सदस्य

संलग्नकः-- यथोक्त।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या 366 / XXXIV / 2014 / 20 / 2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचित, प्रमुख सचिव, एफ0आर0डी0सी0 उत्तराखण्ड शासन।
3. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग भारत सरकार।
4. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड देहरादून।

6 .गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन)
अपर सचिव